



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2004/भाद्र 12, 1926

No. 201]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2004/BHADRA 12, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2004

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : यू. के., जर्मनी, ब्राजील और बुल्गारिया से एक्रिलिक फाइबर के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करना।

सं. 15/18/2004-डीजीएडी.— जबकि 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यू.के., जर्मनी, ब्राजील एवं बुल्गारिया (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध माल कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए 27 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० 42/1/2001-डीजीएडी के द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे।

और जबकि दिनांक 9.10.2002 की अधिसूचना सं० 104/2002 के अनुसार संबद्ध माल पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

## 2. समीक्षा के लिए अनुरोध

नियमों के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निरंतर पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और प्रत्येक से प्राप्त सूचना के आधार पर यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि केन्द्र सरकार को संस्तुत इस प्रकार के शुल्क के सतत अधिरोपण को समाप्त किए जाने का औचित्य नहीं है।

इण्टरनेशनल रेआन और सिंथेटिक फाइबर्स कमेटी (सीआईआरएफएस)- जिन्हें एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है ने क्षति के बारे में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण संबद्ध माल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया है। समीक्षा हेतु किए गए अनुरोध का यूरोपीय आयोग (ईसी) द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया है।

सीआईआरएफएस, जिसने मूल जांच में भाग लिया था, ने इस आधार पर समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया है कि यूरोपीय संघ से किए गए आयातों से कीमतों में कमी नहीं आयी है। अपने अनुरोध के समर्थन में आवेदक ने यूरोपीय निर्यातकों की सी आई एफ कीमत, अपनी उतराई मूल्य और संबद्ध माल की एशियाई कीमतों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। समीक्षा करने की मांग का एक अतिरिक्त आधार भारतीय उद्योग की स्थिति है। आवेदक द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षतिकारक आयातों की अपेक्षा गंभीर असक्षमता के कारण क्षति पहुँची है।

### 3. जांच शुरुआत

परिवर्तित परिस्थितियों का संकेत देते हुए ई यू देशों से हुए आयातों द्वारा कीमत में कमी न होने के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक उत्तर को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह मानना है कि उपर्युक्त नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) के प्रावधानों के अनुसार, परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित है।

27 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं०. 42/1/2001-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात्, निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा नियमानुसार यह समीक्षा करने की शुरुआत करते हैं कि क्या संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के आयातों पर निरंतर शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

### 4. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद एक्रिलिक फाइबर था और वर्तमान समीक्षा के लिए भी विचाराधीन उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, के अध्याय 55 की शीर्ष सं० 5501.30 और 5503.30 तथा आई टी सी एच एस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

### 5. प्रक्रिया

(i) यह समीक्षा नियम 23 के प्रावधानों और उपर्युक्त नियमावली के संगत प्रावधानों के अंतर्गत आएगी। इस समीक्षा में इस तथ्य की जांच करेंगे कि क्या पाटन की क्षति-पूर्ति करने

के लिए शुल्क का अधिरोपण जारी रखना होगा अथवा क्या शुल्क को समाप्त करने, उसमें घट-बढ़ करने अथवा दोनों स्थितियों में क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

(ii) इस समीक्षा में 27 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० 42/1/2001-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं ।

(iii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक है । तथापि, क्षति विश्लेषण में जांच अवधि के अतिरिक्त तीन पूर्ववर्ती वर्षों की अवधि भी शामिल है ।

(iv) इस जांच में शामिल देश यू के, जर्मनी, ब्राजील और बुल्गारिया हैं ।

## 6. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके उच्चायोगों/दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबंधित समझे गए आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने हेतु पृथक रूप से लिखा जा रहा है :-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**

पाटनरोधी शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,

वाणिज्य विभाग,

उद्योग भवन,

नई दिल्ली- 110011

फैक्स सं०. 91-11-23014418

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

## 7. समय-सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि वह इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच सके । यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना नहीं मिलती अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है ।

## 8. सरकारी फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार, कोई हितबद्ध पक्ष अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सरकारी फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

यदि कोई हितबद्ध पक्ष आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो, प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2004

(Mid-term Review)

**Subject : Initiation of Mid-term Review of Anti-dumping duty imposed on imports of Acrylic Fibre from UK, Germany, Brazil and Bulgaria.**

**No. 15/18/2004-DGAD.**— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the Rules), vide Notification No.42/1/2001-DGAD dated 27<sup>th</sup> August, 2002, the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti dumping duty on import of Acrylic Fibre (hereafter referred to as subject goods) originating in or exported from the UK, Germany, Brazil and Bulgaria (hereinafter referred to as subject countries).

AND WHEREAS definitive anti dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No.104/2002 –Customs dated 9<sup>th</sup> October, 2002.

## 2. Request for Review :

WHEREAS the Rules require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied on the basis of information received by that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the Central Government for its withdrawal.

International Rayon and Synthetic Fibres Committee (CIRFS)- hereinafter referred to as applicant has made a request for review of anti dumping duty imposed on imports of subject goods due to changed circumstances with regard to injury. The request for the review has been fully supported by the European Commission (EC).

CIRFS, who had participated in the original investigation, has requested for the review on the grounds that there is absence of price undercutting by imports from European Union. In support of their request, the applicant has furnished information regarding CIF price of European exporters, its landed value and Asian prices of subject goods. An additional ground seeking the review is the situation of the Indian industry. It has been claimed by the applicant that the domestic industry suffers from serious inefficiency rather than injurious imports.

### 3. Initiation :

Having regard to the positive information furnished by the applicant regarding the absence of price undercutting by imports from EU countries indicating changed circumstances, the Designated Authority considers that a Mid-term Review of anti dumping duty imposed as per the aforesaid notification is appropriate in view of the changed circumstances in terms of provisions of Section 9A (5) of the Customs Tariff Act read with Rule 23 of the above Rules.

Having decided to review the final findings issued vide Notification No.42/1/2001-DGAD dated 27<sup>th</sup> August, 2002, the Authority hereby initiates the investigation in terms of the Rules to review whether continued imposition of the duty on imports of subject goods originating in or exported from subject countries is necessary.

### 4. Product under consideration :

The product under consideration in the original investigation was acrylic fibre and for the present review also the product under consideration is acrylic fibre. Acrylic fibre is covered under Heading No.5501.30 and 5503.30 of Chapter 55 of the First Schedule of the Customs Tariff Act and ITC HS Classification. This classification, however, is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

### 5. Procedure :

- (i) This review will be covered by the provisions of Rule 23 and other relevant provisions of the Rules supra. The investigation in this review will determine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.
- (ii) The review will cover all aspects of Notification No. 42/1/2001-DGAD dated 27<sup>th</sup> August, 2002.
- (iii) The period of investigation (POI) for the purpose of the present review will be 1<sup>st</sup> April 2003 to 31<sup>st</sup> March 2004. However, injury analysis shall cover the period of three preceding years also in addition to the POI.
- (iv) The countries involved in this investigation are UK, Germany, Brazil and Bulgaria.

2692 97/04-2

**6. Submission of Information :**

The exporters in subject countries, the Governments of the subject countries through their High Commission/Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the-

The Designated Authority  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Department of Commerce  
Udyog Bhavan  
New Delhi-110011.  
Fax No : 91-11-23014418

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**7. Time Limit :**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

**8. Inspection of Public File :**

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority